‘अप्प दीपो भव’

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2016-18
WPP Licence No.- U(C)-101/2017-18
R.N.I. No. 68180/98

Date of Publication : 15.10.2017
Date of Posting on concessional rate :
2-3 & 16-17 of each fortnight

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन – जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 23354841-42

Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com

● वर्ष : 20 ● अंक 22 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● कुल पृष्ठ संख्या 8 ● 1 से 15 अक्टूबर, 2017

परिसंघ के VOB News24 चैनल का लोकार्पण

30 सितंबर एवं 1 अक्टूबर, 2017 को मावलंकर हॉल, कांस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में को न्याय दिलानें में तथ्यों पर आधारित खबरों के माध्यम से सरकार और अधिकारियों को आगाह करना और में रख कर यह सम्मेलन चला। इस सम्मेलन में देश में चल रहे विभिन्न सरकारी संस्थानों के निजीकरण का

तथागत बुध्द और डॉ. अम्बेडकर की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए डॉ. उदित राज के दाए ओमप्रकाश सिंघवार, सुशील कमल, दामोदर बौध्द, एस. करूपइया व सत्या नारायण तथा बाए सविता कादियान पंवार, मदनराम व तरसेम सिंह घारू

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में एस.सी., एस.टी और ओबीसी अल्पसंख्यकों की आवाज VOB NEWS 24 (वॉयस ऑफ बुद्धा) न्यूज चैनल का लोकार्पण किया गया। जिसका मकसद देश के किसी भी कोने में हो रहे अत्याचार को पूरी निष्पक्षता के साथ रखना और पीड़ित पीड़ित को न्याय दिलाने में मदद करना है। सम्मेलन के मुख्य अतिथि अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का आखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय चेयरमैन डॉ. उदित राज थे। इस कार्यक्रम में देश भर से हजारों की संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता पहुंचे।

देश में दलितों, पिछड़ो, अल्पसंख्यकों की समस्याओं को ध्यान विरोध किया गया एंव निजी क्षेत्रों में आरक्षण व्यवस्था लागू करने की मांग की गई। इन मुद्दों के साथ परिसंघ के चेयरमैन डॉ. उदित राज ने सम्मेलन में आए हजारों कार्यकर्त्ताओं को विभिन्न मुद्दों पर संबोधित किया। डॉ. उदित राज ने कहा कि मैनें पहली बार निजी क्षेत्र मे आरक्षण के लिए संसद में निजी बिल पेश किया जिसके माध्यम से मांग की जा रही है कि सरकार द्वारा लगातार किए जा रहे निजीकरण के चलते दलितों को उसमें भी भागीदारी मिले। इसके साथ ही पदोन्नति और न्यायपालिका तथा सेना में आरक्षण होना चाहिए क्यों कि बाबा साहब का सपना था कि जब हम प्रगति करेंगे तब लोगों को सावधान करते हुए कहा कि आज भी देश में पूरी तरह से संविधान द्वारा प्राप्त आरक्षण पर एस.सी./एस.टी और ओबीसी के पदों को नहीं भरा जाता है जो निहायत ही हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हम सभी लोगों को

VOB न्यूज 24 चैनल का लोकार्पण करते हुए डॉ. उदित राज

कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न प्रदेशों से आए हुए प्रतिनिधिओं के साथ डॉ. उदित राज

हम शासन सत्ता की हकीकत जान सकेंगे जो हमारी समता का एक रास्ता है। वहीं न्यायपालिका में आरक्षण मिलने से समाज में हो रहे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने में सक्षम होगें, जिससे समाज के स्वाभिमान और हितों की रक्षा हो सकती है। इसके साथ खाली पड़े पदों पर एस.सी./एस.टी के लोगों को भर्ती किया जाए ताकि हमारे समाज के लोगों को तरक्की का मौका मिले।

डॉ. उदित राज ने देश के मिलकर लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे साथ कोई भी संगठन जुड़ कर इस मुहिम का हिस्सा बनकर समाज का हित करने में सहयोग कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग यह भ्रम पाल बैठें हैं कि परिसंघ एक राजनैतिक रंग है, इस पर डॉ. उदित राज ने साफ तौर पर कहा कि परिसंघ कोई राजनैतिक दल नहीं है न ही इसे राजनैतिक रूप दिया जाए। हमारे साथ विभिन्न संगठनों के साथी जुड़े हैं। देश में लगातार हो रहे दलित

शेष पृष्ठ 4 पर

परिसंघ की 20वीं महारैली

4 दिसंबर को रामलीला मैदान, नई दिल्ली में

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की 20वीं महारैली आगामी 4 दिसंबर, 2017 (सोमवार) को प्रातः 10 बजे से रामलीला मैदान, नई दिल्ली में आरक्षण सहित अन्य अनुसूचित जाति/जन जाति के अधिकारों के मुद्दों पर होना सुनिश्चित हुई है। परिसंघ के सभी पदाधिकारियों से आग्रह है कि इसकी सफलता के लिए तैयारी अभी से शुरू कर दें। शीघ्र ही इससे संबंधित प्रचार सामाग्री ‘वॉयस ऑफ बुद्धा’ सहित अन्य माध्यमों से आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। रेल से यात्रा करने वाले साथी अभी से ही आरक्षण इत्यादि करवा लें। प्रदेश पदाधिकारियों से आग्रह है कि जिन प्रदेशों में अभी तक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन नहीं हुए हैं, शीघ्र ही करा लें। जहां पर मुझे आने की जरूरत समझें, मैं स्वयं आ सकता हूं।

रैली से संबंधित खबरों से अपडेट रहने के लिए परिसंघ के फेसबुक www.facebook.com/aiparisangh पेज को लाइक करें, ट्वीटर @aiparisangh को फॉलो करें और www.vobnews 24.com भी देखें।

डॉ. उदित राज, राष्ट्रीय चेयरमैन

महारैली की तैयारी बैठक 5 नवंबर को दिल्ली में

5 नवबंर, 2017 को प्रातः 10 बजे स्पीकर हॉल, कांस्टीट्यूशन क्लब, नजदीक पटेल चौक मेट्रो, नई दिल्ली में आगामी महा रैली के संबंध में तैयारी बैठक आयोजित की जा रही है । सभी प्रदेशों के अध्यक्षों, महासचिवों एवं सक्रिय कार्यकर्त्ताओं को इसमें आमंत्रित किया जाता हैं। आपसे आग्रह है कि 4 दिसंबर, 2017 की रैली से संबधित तैयारी की सूचना के साथ अवश्य आयें। VOB New 24 के स्टिंगर/पत्रकार भी आयें ताकि उनका विधिवत प्रशिक्षण किया जा सके। VOB New 24 चैनल से सम्बंधित यदि कोई जानकारी चाहते हैं तों भारत लाल जी मों.7390054024 संपर्क करें।

सावधान : सिंदूर तो सुहागन की बुद्धि ही खत्म कर रहा है

लाइव सिटीज डेस्क : शादी में सबसे खास रस्म क्या है ? वो कौन सा क्षण है जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। यह एक विवाह विधि की ऐसी प्रक्रिया है जिसके बिना शादी ही अधूरी है। यह रस्म सिंदूरदान है। हां एक चुटकी सिंदूर..

उस रस्म के बाद सुहागन का वरदान और जब तक सुहाग है सिंदूर उसका गवाह बना रहता है। यह एक स्त्री को पहचान देता है कि आप शादी शुदा हो। लेकिन सिंदूर क्यों लगाना जरूरी है इनकी जरूरत क्या है इस बात पर बिना सोचे विचारे महिलाएं परंपरा की दुहाई, पति की लंबी उम्र आदि को मान कर लगाये जाती हैं। लेकिन सिंदूर कितना खतरनाक है यह बातें सभी महिलाएं दरकिनार ही कर देती हैं।

ये कहना गलत नहीं होगा कि यहां औरतों के लिए जीवन के हर महत्वपूर्ण कार्यों से बढ़कर जरूरी उसका सिंदूर और तमाम शादी की निशानियां लगाना है। अगर कोई लड़की तार्किक रूप से इसके धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को नकार भी दे तो उसके लिए वैज्ञानिक कारण भी बता दिए जाते हैं। जबकि कई बार रिसर्च की हुई खबरें सामने आती हैं कि सिंदूर से एलर्जी की शिकायत हो सकती हैं। लेकिन अब एक रिपोर्ट की माने तो सिंदूर लगाने से महिलाओं का आईक्यू स्तर घटने का खतरा भी होता है।

अमेरिका की रूजर्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने भारत और अमेरिका के अलग-अलग जगहों से सिंदूर के सैम्पल इकट्ठा कर एक रिसर्च किया है। इस रिसर्च में पाया गया है अमेरिका के 83 फीसदी और भारत के 78 फीसदी नमूनों में प्रति ग्राम सिंदूर में लेड की मात्रा 1 ग्राम पाई गई, जो सामान्य स्तर से ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के फूड एवं ड्रग्स विभाग ने कॉसमेटिक्स में प्रति एक ग्राम 20 माइक्रोग्राम लेड के इस्तेमाल की इजाजत दी है। लेकिन जो सैंपल लिए गए हैं उनमें से अमेरिका से लिए गए 19 फीसदी और भारत से लिए गए 43 फीसदी सैंपल में मात्रा इससे अधिक थी। अमेरिका से लिए गए 3 और भारत से लिए गए 2 सैंपल में तो लेड की मात्रा प्रति 1 ग्राम 10,000 माइक्रोग्राम से भी ज्यादा थी। संस्था ने कहा है कि लेड का कोई भी सेफ लेवल नहीं है, यह किसी भी तरह से हमारे शरीर में नहीं होना चाहिए, खासकर 6 साल की उम्र से नीचे के बच्चों के लिए ये ज्यादा हानिकारक है। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें लेड हो तो वह सेहत के लिए खतरा हो सकता है। लेड की यह मात्रा औरतों और मां के संपर्क में आ रहे बच्चों के शारीरिक और मानसिक परेशानियों का कारण बन सकती है। सिर्फ भारत नहीं देश भर में ऐसी कई मान्यताएं चली आ रही हैं जो औरतों के लिए खतरनाक साबित हो रही हैं। औरतों के पीरियड के दौरान उन पर थोपी जाने वाली वर्जनाएं भी इसी मानसिकता का हिस्सा हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण नेपाल में सालों से चल रही चौपदी प्रथा थी जिसपर अभी कुछ ही दिन पहले रोक लगाई गई है। इन सारी रिपोर्ट और रिसर्च को देखते हुए भी अगर आप किसी महिला के सिंदूर लगाने का विरोध करें तो फिर समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी। औरत पर मानसिक और शारीरिक रूप से खतरा हो तब ठीक है लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक रूढ़ियों पर किसी तरह का खतरा नहीं होना चाहिए।

सिंदूर का रासायनिक संरचना (Chemical composition) :- सिंथेटिक डाई इंडस्टरी कम दाम वाला डाई का इस्तेमाल करके सिंदूर बनाते हैं जो साधारणतः सभी जगह पाये जाते हैं, जिनमें-

सिंगरिफ (cinnabar) पावडर के रूप में होता है जो साधारणतः नारंगी लाल रंग का होता है। रासायनिक डाई और दूसरे सिन्थेटिक तत्व होते हैं

लाल कच्चा सीसा (crude red lead) : पावडर के रूप में होता है, पीबी304 रोडामाइन बी डाई मर्क्यरी सल्फाइट आदि तत्व होते हैं कुछ अनब्रैंडेड लाल रंग के पावडर मिलते हैं जिनके दाम दूसरे सिंदूर के तुलना में कम होते हैं। क्योंकि उत्पादक सिंदूर को सस्ता बनाने के लिए उसमें विषाक्त पदार्थ डालते है जो सिंदूर के रंग को और भी लाल बनाने में सहायता करते हैं। ऐसे सिंदूर नारियों को बहुत आकर्षक लगते हैं और वे इन्हें खरीदने के समय इसमें इस्तेमाल किए गए सामग्रियों को देखते भी नहीं हैं। स्कैल्प और चेहरे के त्वचा पर रैशेज, खुजली, बालों का झड़ना आदि समस्याएं तो होती ही हैं साथ ही महिलाओं का आई क्यू लेवल भी घटता है। बच्चों में मर्क्यरी सल्फाइट के कारण त्वचा कैंसर हो सकता है।

रोडेमाइन बी डाई के कारण (Rhodamine B dye) वंशानुगत विकार (hereditary disorder) हो सकता है खुजली और रूसी की समस्या हो सकती है अगर गलती से खाने में चला गया तो खाना विषाक्त हो सकता है, अगर श्वास-प्रश्वास के साथ चला गया तो मस्तिष्क, किडनी, आँखों और प्रजनन प्रणाली को क्षति पहुँच सकता है। लेड नफ्रापथी (lead nephropathy) हो सकता है

सिंदूर के पार्श्व प्रभाव से कैसे बच सकते हैं :- प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे हल्दी और फिटकरी का इस्तेमाल करके सिंदूर बना सकते हैं। बाजार के सस्ते सिंदूर रूपी पावडर का इस्तेमाल करने से बचे विकल्प के रूप में लाल लिपस्टिक या लाल लाइनर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

विशेष अवसर पर ही सिंदूर लगा सकते हैं

- हर्बल सिंदूर लगा सकते हैं
- कैंसरकारी उत्पादकों से बचें
- नहाने के वक्त गलती से भी सिंदूर मुँह में न चला जाय, इस बात का ध्यान रखें
- सोने से पहले सिंदूर को मेकअप साफ करके ही सोना चाहिए
- बच्चों से बचा कर रखना चाहिए
- माँग में कम-से-कम मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए
- सिंदूर लगाने के बाद हाथ धो लेना चाहिए
- अच्छे ब्रैंड का सिंदूर खरीदना चाहिए जिसमें लेड न हो और खरीदने से पहले सामग्री की सूची जरूर देख लें।

घर पर ही शुद्ध सिंदूर बना सकते हैं-

घर पर आप सिंदूर आसानी से बना सकते हैं, जिसके लिए -

हल्दी

- चूना (slaked lime)
- पानी
- समान मात्रा में एक साथ मिलायें और उसमें जरूरत के अनुसार पानी डालकर पेस्ट बना लें
- पेस्ट को छोटे गोले का रूप दें और धूप में सूखने के लिए छोड़ दें
- सूखने के बाद गोले को पीसकर सिंदूर बना लें

हवाबंद जार में संरक्षित करके रख दें वैश्विक स्तर पर निवारक उपायों पर ध्यान दिया जा रहा है-

कॉज्मेटिक इंडस्ट्री में लेड के हानिकारक तत्वों को कम-से-कम मात्रा में इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। भारतीय मानक ब्यूरो के नियम को पालन करके ही इको चिह्नित उत्पादकों को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कई देशों में जिन कॉज्मेटिक चीजों में लेड है उनके उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसलिए स्थानीय बाजार में खुले में सिंदूर पावडर के विक्रय पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और सिंदूर के पार्श्व प्रभाव से बचने के लिए सिंदूर का इस्तेमाल सावधानीपूर्वक करना सबसे बुद्धिमानी का काम होता है।

http://livecities.in/harmful-sindoor-sindoor-used-in-hindu-ceremonies-could-have-unsafe-lead-levels-harmful-for-women-iq-level-research/

परंपरा के नाम पर मंदिर में लड़कियों को रखा जाता है अर्द्धनग्न, 15 दिनों तक रहना पड़ता है पुजारी की देखरेख में

तमिलनाडु के मदूरै में परंपरा के नाम पर शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां सात लड़कियों को करीब 15 दिनों तक मंदिर के पुजारी के साथ अर्द्धनग्न (टॉपलेस) रखा गया। जब प्रशासन के सामने ये मामला आया कि सात लड़कियों को परंपरा के नाम पर मंदिर में अर्द्धनग्न रखा गया है तो कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी लड़कियों को पूरा शरीर ढंकने के निर्देश दिए। और साथ ही उन्होंने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की, कि इस दौरान उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार तो नहीं हुआ है।

मदुरै के मंदिर के अंदर सातों लड़कियों को पिछले 15 दिनों से अर्द्धनग्न अवस्था में मंदिर में रखा गया था। जहां उन्हें देवी की तरह सजाया गया था। उनके शरीर के ऊपरी हिस्से पर एक भी कपड़ा नहीं था, सिर्फ गहने पहनाए गए थे, और मेकअप किया गया था। इस दौरान उनके साथ मंदिर में सिर्फ पुजारी रहता था जो उनकी देखभाल कर रहा था। मदुरै के कलेक्टर के. वीरा राघव राव ने बताया कि यह काफी पुरानी परंपरा है। घर वाले स्वयं ही अपनी लड़कियों को मंदिर में भेजते हैं। हालांकि प्रशासन ने कपड़े पहनने के निर्देश जारी कर दिए है, और छानबीन करने के आदेश दिए हैं कि इस दौरान उनके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी या दुर्व्यवहार तो नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों की एक टीम मौके पर जांच-पड़ताल के लिए गई थी, लेकिन मंदिर में बच्चों के साथ किसी प्रकार के दुर्व्यवहार की बात सामने नहीं आई। कलेक्टर ने इस दौरान लोगों को निर्देश दिए हैं कि लड़कियों के शरीर परंपरा के दौरान पूरी तरह से ढंके हों।

इस इलाके में 60 से अधिक गांव इस परंपरा में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, जिसमें किशोरियां देवी जैसी पूजी जाती हैं। हैरानी इस बात पर है कि लड़कियों के परिवार वाले खुद अपनी बेटियों को परंपरा के नाम पर बिना कपड़ों में रहने की इजाजत दे देते हैं। और परंपरा और आस्था के नाम पर मासूम बेटियों को 15 दिनों तक अर्द्धनग्न अवस्था में पुजारी के साथ मंदिर में रहने देते हैं।

http://padtal.com/news/news_detail/Girls-were-forced-to-bare-chest-in-madurai-temple

नये शोध ने साबित किया, आर्य बाहर से आए थे

दयानंद द्विवेदी

नये डीएनए साक्ष्य भारतीय इतिहास के सबसे विवादित प्रश्न का समाधान कर रहे हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जवाब कितना प्रामाणिक है। लिख रहे हैं टोनी जोसेफ

एक पेचींदा मामला, जिस पर भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा बहस हुई है, अपना जवाब धीरे-धीरे लेकिन प्रामाणिक रूप से हासिल कर रहा है। क्या भारतीय-यूरोपीय भाषा बोलने वाले, जिन्होंने खुद को आर्य कहा, भारत में लगभग 2000 ई.पू. -1500 ई.पू. आये थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गयी थी, और अपने साथ संस्कृत भाषा तथा एक खास तरह की सांस्कृतिक परम्परा लेकर आये थे? आनुवांशिक अनुसंधान के आधार पर नये डीएनए साक्ष्य दुनिया भर के वैज्ञानिकों को स्पष्ट रूप से एक जवाब की ओर इशारा कर रहे हैंः हां, उन्होंने ऐसा किया।

बहुतों के लिए यह एक आश्चर्य हो सकता है, कुछ के लिए यह एक सदमा हो सकता है, क्योंकि हाल के वर्षों में प्रमुख आख्यान यह रहा है कि आनुवंशिकीय अनुसंधान ने आर्यों के देशांतर गमन के सिद्धांत को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। यह व्याख्या एक अतिरंजना की कोशिश थी क्योंकि जो भी इन वैज्ञानिक शोध पत्रों को मूल में पढ़ा है, वह जानता है। लेकिन वाई-गुणसूत्रों (या ऐसे गुण सूत्र जो कि पुरुष पैतृक वंश, पिता से पुत्र, के माध्यम से हस्तांतरित होते हैं) पर आई नये आंकड़ों की बाढ़ ने इस अवधारणा को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है।

वंश अवरोहण का क्रम

अभी हाल तक, केवल एमटी डीएनए (या मातृ वंश डीएनए, जो कि मां से पुत्री की ओर हस्तांतरित होता है) पर आंकड़े उपलब्ध थे जो कि इस तरफ इशारा करते थे कि पिछले 12,500 वर्षों से या लगभग इसी प्रकार के समय से भारतीय जीन पूल में बहुत ही कम बाहरी सम्मिश्रण हुआ है। नये वाई-गुणसूत्र के आंकड़े ने इस बात के पक्के सबूत दिये हैं कि विवादित अवधि के दौरान भारतीय पुरुष वंशावली में बाहरी जीन का सम्मिश्रण हुआ है, जिससे पहले का निष्कर्ष उलट गया है।

यदि हम पीछे मुड़कर एक नजर डालें तो हम पायेंगे कि एमटी डीएनए तथा वाई-डीएनए में यह अंतर एकदम वाजिब है। कांस्य युग के विस्थापन में लिंग पक्षपात मजबूती के साथ मौजूद था। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि जिन्होंने विस्थापन किया वे प्रमुख रूप से पुरुष थे और इसलिए जो जीन हस्तांतरित हुए, वे एमटी डीएनए में दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसके विपरीत, ये वाई-डीएनए के आंकड़ों में दिखाई पड़ते हैंः विशेष रूप से, लगभग 17.5 प्रतिशत भारतीय पुरुष वंशावली को हैप्लो ग्रुप आर 1 ए (हैपलो ग्रुप्स वंश अवरोहण के एकरेखीय क्रम को बताते हैं) से संबंधित पाये गये हैं जो कि आज मध्य एशिया, यूरोप तथा दक्षिण एशिया में फैले हुए हैं। पोंटिक-कैस्पियाई स्टेपी एक ऐसा क्षेत्र था जहां से आर 1ए पश्चिम एवं पूर्व दोनों ओर फैला जिसमें कि बाद में दो उप शाखाएं बनीं।

वह शोध पत्र जो कि अभी हाल के सारे खोजों को भारत में विस्थापन के एक सुव्यवस्थित तथा ठोस इतिहास के रूप में रखता है, का प्रकाशन एक अग्रणी जर्नल 'बीएमसी इवोल्यूशन रीबायोलॉजी' में महज तीन माह पूर्व हुआ था। उस शोध पत्र में, जिसका शीर्षक था ''एजिनेटिक क्रोनोलॉजी फॉर द इंडियन सबकंटिनेंट प्वाइंट्स टू हेवी इलीसेक्स-बॉयस्ड डिस्पर्सल्स'', प्रो. मार्टिन पी.रिचर्ड्स, हडर्स फील्ड विश्वविद्यालय, यूके के नेतृत्व में 16 वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह निष्कर्ष निकाला कि ''कांस्य-युग में मध्य एशिया से आनुवंशिकीय अंतः प्रवाह प्रमुख तौर पर पुरुष आधारित था, जो कि पितृ सत्तात्मक सामाजिक ढांचे के संगत था जैसा कि पहले का भारतीय-यूरोपीय समाज चरवाहे का काम प्रमुख तौर पर करता था। यह भारतीय-यूरोपीय विस्तार की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा था, जिसका बुनियादी स्रोत पोंटिक-कैस्पियाई क्षेत्र था तथा जिसने वाई-गुणसूत्र वंशावली को सबसे निकट से यूरेशिया (यूरोप-एशिया) में 5000 तथा 3,500 वर्ष पूर्व आगे बढ़ाया''।

एक ई-मेल के जवाब में, प्रो.रिचर्ड्स ने कहा कि भारत में आर 1ए की प्रमुखता ''बहुत सुदृढ़ साक्ष्य हैं कि मध्य एशिया से पर्याप्त मात्रा में कांस्य-कालीन विस्थापन हुआ जो कि भारतीय-यूरोपीय भाषियों को भारत में लाया। प्रो.रिचर्ड्स तथा उनकी टीम का यह शक्तिशाली निष्कर्ष, पूरी दुनिया भर में आनुवंशिकी वैज्ञानिकों के कार्यों के माध्यम से अभी हाल के वर्षों में उपलब्ध नये आंकड़ों तथा निष्कर्षों के विस्तृत खजाने तथा उनके अपने स्वतंत्र अनुसंधान का नतीजा है। पीटर अंडरहिल, स्टैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में आनुवंशिकी विभाग में वैज्ञानिक, इस कार्य को करने वालों में से एक थे। तीन साल पहले, 32 वैज्ञानिकों की एक टीम का उन्होंने नेतृत्व किया तथा आर 1ए के वितरण तथा वंशावली के चित्रण का एक व्यापक अध्ययन प्रकाशित किया था। इसने पूरे यूरेशिया से 126 जनसमुदायों से 16,244 पुरुष व्यक्तियों के एक पैनल का उपयोग किया। डॉ. अंडरहिल के अनुसंधान ने यह पाया कि आर 1ए के दो सब-हैप्लोग्रुप्स हैं जिसमें कि एक प्रमुख तौर पर यूरोप में पाया जाता है तथा दूसरा मध्य तथा दक्षिण एशिया में परिसीमित था। यूरोप में आर 1ए नमूनों के छियानबे प्रतिशत नमूने सब-हैपलोग्रुप्स जेड 282 से संबंधित हैं जबकि मध्य तथा दक्षिण एशिया आर 1ए वंशावली का 98.4 प्रतिशत नमूने सब-हैपलोग्रुप्स जेड 93 से संबंधित है। ये दोनों ग्रुप्स सिर्फ 5,800 वर्ष पूर्व जाकर ही एक दूसरे से पृथक होकर अलग-अलग दिशाओं में गये। डॉ. अंडरहिल के अनुसंधान ने जेड 93 के अंदर यह दर्शाया है कि यह भारत में प्रमुख तौर पर था, आगे यह फिर कई शाखाओं में विभाजित हो गया। शोध पत्र में यह पाया गया है कि यह ''तारों सदृश प्रशाखन'' त्वरित विकास तथा छितराव का निर्देशन था। इसलिए, यदि आप वह अनुमानित समय जानना चाहते हैं जब भारतीय-यूरोपीय भाषा बोलने आये और भारत में तेजी से फैल गये, तो आपको उस तारीख की खोज करनी पड़ेगी जब जेड 93 अपने विभिन्न उप-समूहों या वंशावली में विभाजित हुआ। हम इसकी चर्चा बाद में करेंगे।

इसलिए, यदि हम संक्षेप में कहें तो आर 1ए पूरे यूरोप, मध्य एशिया तथा दक्षिण एशिया में फैला हुआ है, इसका उप-समूह जेड 282 केवल यूरोप में फैला है जबकि इसका दूसरा उप-समूह जेड 93 केवल मध्य एशिया तथा दक्षिण एशिया के हिस्सों में ही फैला है तथा जेड 93 के तीन प्रमुख उप-समूह केवल में भारत, पाकिस्तान तथा हिमालय के क्षेत्रों में प्रसारित हैं। आर 1ए के वितरण की इस स्पष्ट स्वीकार ने पहले की परिकल्पना पर पूर्णरूप से विराम लगा दिया है कि इस हैपलो ग्रुप का उद्गम स्थल भारत है तथा बाद में यह बाहर फैला। यह परिकल्पना एक गलत अनुमान पर आधारित थी कि भारत में आर1 वंशावली में अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी विविधता थी जो कि इस बात का संकेत हो सकती थी कि इसका उद्गम स्थल यहां है। जैसा कि प्रो. रिचर्ड्स कहते हैं कि ''यह विचार कि आर1ए भारत में बहुत विविधतापूर्ण है, जो कि बड़े पैमाने पर अस्पष्ट माइक्रो सेटलाइट डेटा पर आधारित था, नये आनुवंशिक वाई गुण सूत्रों के आंकड़ों के बड़े पैमाने पर आने के बाद समाप्त हो गया है''।

जीन-विस्थापन की तारीख का निर्धारण :

अब हमें यह मालूम है कि कांस्य-युग में मध्य एशिया से भारत में पर्याप्त मात्रा में जीन का आगमन हुआ था, क्या हम समय को बेहतर तरीके से निर्धारित कर सकते हैं, विशेष रूप से जबकि जेड 93 का इसकी अपनी उप-वंशावलियों में विभाजन हुआ? हां, हम ऐसा कर सकते हैं। शोध पत्र यह दर्शाते हैं कि इस सवाल का जवाब अभी पिछले वर्ष अप्रैल 2016 में प्रकाशित हुआ था जिसका शीर्षक था ''1,244 विश्वव्यापी वाई-गुण सूत्रों के अनुक्रम से निष्कर्षित मानव पुरुष जनसांख्यिकी में निर्धारक तथ्य (पंक्चुएटेड ब्रस्ट्स इन ह्युमन मेल डेमोग्राफी इनफर्ड फ्राम 1,244 वर्ल्ड वाइड वाई-क्रोमोजोम्स सीक्वेंसेज)''। इस शोधपत्र, जो कि पांच महाद्वीप जनसंख्या के अंदर वाई-डीएनए हैप्लोग्रुप्स के प्रमुख विस्तार पर विचार करता है, को डा. अंडरहिल के साथ डेविड पोजनिक, स्टैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि 42 सह-लेखकों में से हैं, द्वारा प्रमुख रूप से लिखा गया है। इस अध्ययन में यह पाया गया है कि जेड 93 के अंदर सबसे महत्वपूर्ण विस्तार लगभग 4,000 से 4,500 वर्ष पूर्व हुआ। यह उल्लेखनीय है क्योंकि मोटे तौर पर लगभग 4,000 वर्ष वह समय था पहले सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की शुरुआत हो गयी थी। (अभी तक पुरातत्वीय या किसी अन्य प्रकार से इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि एक के पतन से दूसरी सभ्यता की शुरुआत हुई, बहुत संभव है कि एक समय में ही हुई हो)।

बड़ी तादाद में आये नये आंकड़े इतने जबर्दस्त हैं कि कई वैज्ञानिकों, जो कि कांस्य युग के विस्थापन के बारे में संदेहास्पद या तटस्थ थे, ने अपने विचार बदल लिये हैं। डॉ. अंडरहिल स्वयं उसमें से एक है। उदाहरणार्थ, वर्ष 2010 के एक शोधपत्र में, उन्होंने लिखा है कि पूर्व में पिछली पांच या छह सहस्राब्दी में ''पूर्वी यूरोप से एशिया-भारत सहित की ओर पर्याप्त पुरुष वंशावली के जीन के प्रवाह ''के विरुद्ध साक्ष्य थे। लेकिन आज डॉ. अंडरहिल कहते हैं कि वर्ष 2010 के आंकड़ों तथा अब के उपलब्ध आंकड़ों में कोई तुलना ही नहीं है। '' उस समय के आंकड़े इस तरह से थे जैसे कि एक अंधेरे कमरे में हाथ में एक टार्च लेकर एक होल से देखा जाय, आप केवल एक कोना देख सकते हैं लेकिन पूरा कमरा आपको नहीं दिखायी पड़ सकता है, सम्पूर्ण जीन को हम एक अनुक्रम में बांध कर हम एक बेहतर प्रकाश में अब लगभग पूरा कमरा देखने में सक्षम हैं''। डॉ. अंडरहिल ही केवल ऐसे नहीं हैं जिनके पुराने काम को कांस्य-युग में भारतीय-यूरोपीय भाषा बोलने वालों के भारत में प्रव्रजन के विरुद्ध प्रयुक्त किया गया है। डेविड रिच, आनुवंशिकी वैज्ञानिक, जो कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में आनुवंशिकी विभाग में प्रोफेसर हैं, ऐसे दूसरे व्यक्ति हैं, हालांकि, अपने पुराने शोधपत्रों में उन्होंने बहुत सावधानी बरती है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण 2009 में प्रकाशित एक अध्ययन हैं जिसके प्रमुख लेखक डेविड रिच हैं, अध्ययन का शीर्षक है ''रीकंस्ट्रक्टिंग इंडियन पॉपुलेशन हिस्ट्री'' जो 'नेचर' में प्रकाशित हुआ। इस अध्ययन ने भारतीय जनसमुदाय के आनुवंशिकीय उप संरचना की खोज के लिए सैद्धांतिक रचना 'एन्सेस्ट्रल नॉर्थ इंडियंस'(एएनआई) तथा 'एनसेस्ट्रल साउथ इंडियन्स' (एएसआई) का प्रयोग किया। अध्ययन ने प्रमाणित किया कि एएनआई आनुवंशिकीय रूप से मध्य-पूर्व, मध्य एशिया के लोगों तथा यूरोपियन से घनिष्ठ रूप से संबंधित है जबकि एएसआई केवल भारत में ही विशिष्ट रूप से पाये जाते थे। अध्ययन ने यह भी प्रमाणित किया है कि अनुमान लगाया जा सकता है कि आज भारत में कई समूह इन दो जन समुदायों का एक सम्मिश्रण हैं, जिसमें कि एएनआई वंशावली परम्परागत रूप से ऊंची जाति है तथा भारतीय-यूरोपीय भाषा बोलने वाले हैं। यह अध्ययन स्वयं में भारतीय-यूरोपीय भाषियों के यहां पहुंचने को अस्वीकार नहीं करता है, यदि कोई बात जो यह बताता है तो यह उसके विपरीत एएनआई का मध्य एशिया से आनुवंशिकीय श्रृंखलात्मक जुड़ाव है।

हालांकि, इस सैद्धांतिक ढांचें को तर्क से परे जाकर समझा गया और यह दलील दी गयी कि ये दोनों समूह भारत में सहस्राब्दियों पहले आये थे, उस समय से बहुत पूर्व जबकि भारतीय-यूरोपीय भाषियों का प्रव्रजन हुआ जो कि लगभग 4000 से 3500 वर्ष पूर्व हुआ। असल में, अध्ययन ने एक बड़ी चेतावनी शामिल किया है जो कि इसके विपरीत बात कहती है। ''हम चेतावनी देते हैं कि जन समुदाय आनुवंशिकी में 'मॉडल्स को चेतावनी के साथ लिया जाना चाहिए। जबकि वे ऐतिहासिक परिकल्पना के परीक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा उपलब्ध कराते हैं, वे अतिसरलीकरण हैं। उदाहरणार्थ, वंशावली जन समुदाय (ऐनसेस्ट्रल पॉपुलेशन) वास्तविकता में संभवतः सजातीय नहीं थे जैसा कि हम अपने मॉडल में मानते हैं बल्कि इसके स्थान पर इस बात की संभावना है कि वे विभिन्न काल खंड में सम्मिश्रित होने वाले संबंधित समूहों के क्लसटर्स द्वारा सृजित हुये ''। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि इस बात की संभावना है कि एएनआई बहु-विस्थापन का परिणाम है, संभवतः जिसमें भारतीय-यूरोपीय भाषियों का विस्थापन शामिल है।

http://janchowk.com/ART-CULTUR-SOCIETY/arya-visthapan-research-centralasia-europe/512

***

परिसंघ के VOB News24 चैनल .....

पृष्ठ 1 का शेष

उत्पीड़न पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आज जो VOB NEWS 24(वॉयस ऑफ बुद्धा) न्यूज चैनल का मेरे द्वारा उद्घाटन हुआ है। मुझे आशा और विश्वास है कि पूरे देश में जिस तरह से दलितों पर अत्याचार कुछ तथा कथित मनुवादी संगठन कर रहे हैं उनको पूरी निष्पक्षता से दिखाने का काम करेगा । साथ ही सरकार द्वारा विभिन्न तरह से चाहे आरक्षण का मुद्दा उठाना हो न्याय में देरी, सरकारी योजनाओं का लाभार्थियों को लाभ न मिल पाना, एससी एक्ट के तहत अपराधियों पर कार्रवाई न करना, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जोड़ कर लोगों को जागरूक करना होगा । जिसके तहत पीड़ितों, शोषितों व वंचितों को लाभ मिल सके। हमें पूरा विश्वास है कि VOB NEWS 24 हमारे समाज के मुद्दों को पूरी मजबूती से रखेगा, वही उन्होने कहा अभी तक हमारे समाज के समर्थन में कोई मीडिया चैनल नहीं आया था। आज हम VOB NEWS 24 चैनल का लोकार्पण कर अपने को गौरवांवित महसूस कर रहें हैं।

इस मौके पर परिसंघ के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सुशील कुमार कमल ने कहा कि VOB NEWS 24 (वॉयस ऑफ बुद्धा) का जो आज भव्य लोकार्पण हुआ है बहुत ही समाज के लिए गर्व का विषय है। हमें इस चौनल को आगे लेकर जाना है जो सरकार तक हमारी बातों को पूरी मजबूती से रख सके और समाज में हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने में सक्षम हो। इसके लिए हम सभी लोगों को सबसे पहले सोशल मीडिया से जुड़ना होगा तभी हम देश में हो रही गतिविधियों को हकीकत में समय से जान सकते हैं। क्योंकि आज-कल सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफार्म है, जहां से हम अपनी बातों को रख सकते हैं। इस लिए हमें VOB NEWS 24 का तन, मन व धन से सहयोग करते हुए सफल बनाए रखना है। श्री कमल ने कहा कि आज सोशल मीडिया का चलन है। देश में हो रहे दलित समाज पर विभिन्न तरह से अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वाले परिसंघ के चेयरमैन डॉ. उदित राज जी द्वारा समय-समय पर यूट्यूब और फेसबुक, ट्वीट के जरिए संदेश मिलते हैं, जिन्हें हमें पूरी तरह सक्रिय होकर देखना है। हर रोज ज्वलंत मुद्दों पर परिसंघ के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, संदेश देखे व सुने जा सकते हैं, श्री सुशील कमल ने अपील किया कि सभी लोग परिसंघ के चेयरमैन, डॉ. उदित राज जी के संदेशों को लाइक करने के साथ सबसे ज्यादा शेयर करें, तथा सुझाव भी भेजते रहें। आज का समय सोशल मीडिया का है जिससे हमें तेजी से जुड़ना होगा ताकि हम देश में हो रही किसी भी तरह की गतिविधियों, षड्यंत्रों से सावधान रह सकें। इस लिए आप सभी लोग परिसंघ के संदेशों को अवश्य पढ़े और शेयर करें ताकि एस.सी./एस.टी और ओबीसी तथा अल्पसंख्यक समाज के हर कोने तक इसका प्रभाव हो। इस माध्यम से हम अपने स्वाभिमान व सम्मान की रक्षा कर सकते हैं।

परिसंघ के चेयरमैन डॉ. उदित राज जी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आज देश में सबसे ज्यादा एस.सी./एस.टी और ओबीसी के लोगों की संख्या है, ज्यादातर सभी लोग फोन यूज करते हैं सोशल मीडिया से भी जुड़े हैं लेकिन सबसे ज्यादा शर्म की बात तो यह है कि हमारे लोग सोशल मीडिया का प्रयोग बहुत कुछ अपने मित्रों, संबंधियों को हैलो हाय लिखने-पढ़ने के लिए ही करते हैं, जो एक गंभीर विषय हैं। जबकि अन्य समुदाय के लोग आरक्षण को समाप्त करने के लिए दिन रात तमाम तरह के मैसेज एक दूसरे को भेजते हैं, साथ ही सबसे ज्यादा तो मैसेज आडम्बर के होते हैं। रोज नए और झूठे मैसेज ऐसे लोगों द्वारा भेजें जाते हैं, हमारे लोग पढ़ कर कोई जबाव नहीं देते। उन्होंने कहा कि हमारे लोग तर्कहीन बने रहते हैं, क्योंकि परिसंघ जो देश में तमाम तरह के मुद्दे एस.सी./ और ओबीसी अल्पसंख्यकों के हितों के लिए उठा रहा है उसने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर कोई रिप्लाई नहीं आता इससे साफ पता चलता है कि लोग आज भी गफलत की मानसिकता में जी रहे हैं। हमें जागना होगा कहीं देर न हो जाए कि हम सोते रहें और सब लुट जाए और जब हम देखें और पढ़ें तब तक बहुत देर न हो चुकी हो इन बातों पर डॉ. उदित राज जी ने प्रकाश डाला ।

दूसरे दिन के सम्मेलन में भी तमाम समस्याओं पर चर्चा की गई जिसमें नारी सशक्तीकरण, परिसंघ की उपलब्धियां, परिसंघ के प्रमुख मुद्दे, सोशल मीडिया से जुड़ाव,एस.सी./एस.टी. और ओबीसी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, जातीय भेदभाव, परिसंघ के खिलाफ षड्यंत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, न्याय, नौकरी, रोजगार आदि मुद्दों पर परिसंघ के चेयरमैन डॉ. उदित राज जी के अलावा कई वक्ताओं ने प्रकाश डाला। डॉ. उदित राज ने कहा कि देश का उत्थान तभी संभव है जब महिलाओं की बराबरी की भागीदारी सभी क्षेत्रों में होगी। महिला सशक्तिकरण के नाम पर केवल भाषणबाजी नहीं होनी चाहिए बल्कि सभी को अपने घरों में साक्षात करनी होगी। महिलाएं हमारे समाज में केवल उपभोग की वस्तु नहीं हैं वल्कि हमारे परिवार के विकास की उत्पादन कर्ता हैं। आज देश में महिलाओं की हिस्सेदारी पर पुरुष वर्ग का कब्जा बना हुआ है खास कर राजनीतिक, और व्यापारिक क्षेत्र में हालत तो बद से बदतर हैं। राजनीति के संवैधानिक पदों पर महिलाओं का नाम होता है पर पुरुष वर्ग अपनी सत्ता को जबरन स्थापित करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा अधिकारी जिम्मेदार होते हैं जो परिवारिक पुरुष प्रतिनिधित्व स्वीकार करते हैं जो संविधान के मूलरूप और बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर के सपनों के खिलाफ हैं। भारत के शिक्षा गुरु महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी माता सवित्रीबाई फुले को शिक्षित किया और प्रेरित करते हुए स्वयं महिलाओं को पढ़ानें के लिए विद्यालय खुलवाया ताकि महिलाएं शिक्षित हो सकें और राष्ट्र के विकास में बराबरी की भागेदारी रहे। इस मौके पर महिलाओं के मसीहा बाबा साहब द्वारा महिलाओं के लिए किए गए बलिदानों को भी याद दिलाया गया। आज देश में महिलाओं के हक व सम्मान की बात कर रहे हैं, ये सब बाबा साहब का सपना है जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, ''तब तक लड़ेंगे-जब तक हम कामयाब न हो जाएं।''

सम्मेलन के दूसरे दिन परिसघ के संगठन में भी विस्तार किया गया। जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, हरियाणा की इकाईयों में परिवर्तन के साथ पुराने पदाधिकारियों को पदोन्नत किया गया ताकि संगठन को विस्तारात्मक और ज्यादा गति मिले। श्री ओम प्रकाश सिंघमार को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। आगामी समय में परिसंघ और मजबूत हो इसके लिए सभी पदाधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए कि सभी लोग आगामी तय बैठक में यह ब्योरा पेश करेंगे कि आपने कितनी बैठकें की साथ ही कितने लोगों को परिसंघ से जोड़ा। जिसके लिए समय-समय पर मानीटरिंग की जाएगी। बैठक में देश भर से आए पदाधिकारियों को परिसंघ की तरफ से एक रजिस्टर दिया गया है जिसमें कार्रवाई भरना है। जिससे यह तय हो सके कि पदाधिकारी ने क्या काम किया इसके साथ परिसंघ को कितनी मजबूती मिली।

चेयरमैन डॉ. उदित राज ने साफ शब्दों में कहा कि बैठकों के नाम पर खानापूर्ति नहीं की जाए बल्कि परिसंघ के मिशन से लोगों को जोड़ा जाए ताकि हम संख्या बल के आधार पर केन्द्र व देश की राज्य सरकारों पर दलितों के मुद्दों पर दबाव बनाया जा सके। परिसंघ का उद्देश्य मुख्यतः षड्यंत्रकारियों द्वारा संविधान में संशोधन कर आरक्षण पर कुठाराघात करना है उसे रोकना है। साथ ही संविधान द्वारा प्रदत्त पूर्ण आरक्षण को लागू करने का है। जो आजादी के बाद से केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा ईमानदारी से कभी लागू नहीं किया गया है। लोग आरक्षण खत्म करने की बात तो करते हैं लेकिन जाति खत्म करने की वकालत कोई नेता या संगठन नहीं करता। हमें आरक्षण के रूप में सरकार भीख नहीं दे रही बल्कि यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन सरकारें हमारे अधिकार में लगातार कटौती करती आई हैं जिसके फलस्वरूप आज भी हमारा दलित समाज पिछड़ा है। सरकार के नेता लगातार आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं लेकिन कभी भी किसी मंच पर जाति खत्म करने की बात नहीं करते हैं। ये कैसा दोहरा चरित्र है। सरकारी संस्थानों के निजीकरण के पीछे एक और कारण है कि कुछ लोग किसी तरह से कार्यपालिका पर काबिज होना चाहते हैं, ताकि किसी तरह से भारत की आर्थिक व्यवस्था को काबू करके देश में शोषित पीड़ित समाज को फिर से गुलाम बना लें । श्री राज ने इस ओर देश को एस.सी./एस.टी., ओबीसी और अल्पसंख्यकों को गंभीरता से ध्यान देना होगा कि ये लोग भारत में उसी तरह से प्रवेश कर रहे हैं जिस तरह से अंग्रेजों ने व्यापार स्थापित करने के रूप में किया और आर्थिक संपन्नता आनें पर देश की अर्थ व्यवस्था को कब्जे में लेकर देश के लोगों को गुलाम बनाया था। सरकारी संस्थानों के निजीकरण से ये आरक्षण विरोधी लोग भारत की आर्थिक व्यवस्था को कब्जे में लेकर फिर से दलितों, पिछड़ों, शोषितों, अल्पसंख्यकों को गुलाम बनाया जा रहा है जिसका मकसद किसी तरह से देश में अपनी मनुवादी सत्ता बनाए रखना है। लेकिन हम ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों को कामयाब नहीं होने देंगें। VOB NEWS 24 (वॉयस ऑफ बुद्धा) न्यूज चैनल के लोकार्पण के मौके पर चैनल हैड भरत लाल जी ने घोषणा की जल्द ही VOB NEWS 24 सैटेलाइट पर आने वाला है जिसकी तैयारी पूरी है। संबंधित विभागीय कार्रवाई जारी है, बहुत ही जल्द भारत के सभी क्षेत्रों में चैनल का प्रसारण किया जाएगा।

अनुसूचित जाति-जन जाति संगठनो का अखिल भारतीय परिसंघ के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन पर परिसंघ के चेयरमैन डॉ. उदित राज, उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सुशील कुमार कमल, नीरज चक, बिहार प्रदेश इकाई के अध्यक्ष मदन राम, अमर ज्योती, आनन्द वर्धन, शिवधर पासवान, सदानन्द पासवान, अनुरागी पासवान, कनार्टक से जी. श्रीनिवासन, हिमाचल से सीताराम बंसल, निहाल सिंह निहालता, बंगाल प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पी. बाला, सुब्रता बातूल, मनीमोहन बिश्वास, सदन नस्कर, उड़ीसा से दीलिप कुमार बेहेरा, नारायण चरण दास, मध्यप्रदेश से परम हंस प्रसाद, नरेन्द्र चौधरी, गुजरात से मुकेश गोसवी तमीलनाडु से एस. करूपइया डी. रविचन्द्रन, के. रविचन्द्रन, केरल से रमन बाला कृष्णन, के.टी. जॉन्सस, मनीपुर से रेव लंघु हिलेरी, तेलंगाणा से महेश्वर राज, माधव राव, छत्तीसगढ़ से हर्ष मेश्ररराम , महाराष्ट्र इकाई प्रदेश अध्यक्ष सिध्दार्थ भोजने, संजय कांबले बापेकर, महेन्द्र सालवे, अजय मनवर, बालासाहेब कांबले, प्रो. सतीश वागरे, झारखण्ड से मधुसूदन कुमार, एच. सी. भगत, एल. एम. ओराव, प्रदीप सुखदेव, जे एण्ड के से आर. के. कलसोत्रा, बी.एल. भारतवाज, अमरनाथ भगत, रमेश चन्द, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सत्यप्रकाश जरावता, राजेन्द्र प्रसाद, डॉ. शिवकुमार, सत्यावान भाटीया, वजीर सिंह मेहरा पंजाब से तरसेम सिंह घारू, रोहित सोनकर, दिल्ली से, सत्यानारायण, राजस्थान से विश्वराम मीणा, पंचमराम, उत्तराखंड से विजय राज अहिरवार, महावीर सिंह, सविता कादियान पवार (राष्ट्रीय संयोजिका महिला प्रकोष्ठ), अर्चना भोयर (राष्ट्रीय सह संयोजिका महिला प्रकोष्ठ), डॉ. गुंजन, एअर इंडिया की पायलट बाबी, निर्देश कुमारी (मुरादाबाद), ममता (गोंडा), कुसुम लता, सुनीता, रीता सरकार, मीना भारती (जिला पंचायत सदस्य बांदा-यूपी) ने सम्मेलन में शिरकत किया। दिल्ली परिसंघ केन्द्रीय कार्यालय के प्रभारी सुमित कुमार, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष संजय राज, खटीक सेना के राष्ट्रीय महासचिव इन्द्रेश चन्द खटीक, सोशल मीडिया इंचार्ज गणेश येरेकर आदि लोग मौजूद रहे । इस मौके पर VOB NEWS 24 (वॉयस ऑफ बुद्धा) न्यूज चैनल के चैनल हेड भरत लाल जी, संजय पाल (रिशर्च इंजीनियर आईटी सेल), प्रदीप शिवहरे (डायरेक्टर), प्रशान्त राव गौतम ''निराला''(चीफ एडिटर), अजीत कुमार कमल(लाइव स्ट्रीमिंग), विवेक सिंह

शेष पृष्ठ 6 पर

मंच पर बैठे डॉ. उदित राज जी बाए आर्चना भोयर एवं दाएं बॉबी पायलट, सी.पी.सोनी, ओमप्रकाश सिंघमार, एवं पिछली पंक्ति में सुशील कमल, डी. हर्षवर्धन, परमेंद्र, बाबू लाल, सत्या नारायण, एम.एस. लाकरा व अन्य

जातीय भेदभाव और विकास का संबंध

डॉ. उदित राज

दलित उत्पीड़न हो या महिलाओं के साथ भेदभाव इसका सीधा संबंध विकास से नहीं है। पिछड़े इलाकों में भी भेदभाव कम हो सकता है और विकसित में ज्यादा। अगर हम घटनाओं के बारे में विश्लेषण करें तो यह बात प्रमाणिकता से कही जा सकती है। हाल में दो घटनाएं गुजरात में हुईं। पहली, गांधी नगर के कालोल तालुका के लिंबोदरा गांव के रहने वाले 24 वर्षीय पीयूष परमार को इंग्लिश स्टाइल में मूंछ रखने पर पीटा गया है। दूसरी, गुजरात के ही आणंद जिले के बदरनिया में एक 21 वर्षीय दलित, जयेश सोलंकी जो गरबा डांस देखने गया था कि पटेल समाज के लोग यह सहन न कर सके और उसे मार-मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। यह सर्वविदित है कि गुजरात विकसित राज्यों में से एक है। प्रश्न यह उठता है कि जो आर्थिक रूप से संपन्न और शिक्षित हैं, वे भी अवसर मिलने पर भेदभाव करने से चूकते नहीं। एक प्रश्न जो सबसे ज्यादा चिंतित करता है कि क्या जिनके साथ में भेदभाव होता है, वही प्रतिरोध करें? क्या ऐसी घटनाएं कमजोर वर्ग को ही प्रभावित करती हैं? क्या इसका संबंध देश के विकास से नहीं है? क्या सरकार द्वारा चलाए गए तमाम अभियान, जैसे – स्वच्छ भारत आदि पर इसका प्रतिकूल असर नहीं पड़ता?

जो मानसिकता इन्हें पिछड़े और दबे के रूप में देखना चाहती है, वही देश को भी आगे नहीं जाने देना चाहती है। यह राष्ट्रीय विषय है न कि केवल सामाजिक न्याय या दबे कुचले जनप्रतिनिधियों का ही। महिलाओं की आबादी लगभग आधी है और जब तक भेदभाव रहेगा तब तक उनकी भागीदारी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आर्थिक क्षेत्र में कम ही रहेगी। इसका सीधा असर सभी आर्थिक क्षेत्रों में पड़ेगा, चाहे वह कृषि हो या उत्पादन या सेवा इत्यादि। यदि इनकी क्रयशक्ति कम होती है तो वस्तुओं की खरीदारी कम होगी और हमारा उत्पादन क्षेत्र ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्र जैसे सेवा इत्यादि भी प्रभावित होगें।

आजादी के 70 साल हो गए, फिर भी सरकारें नहीं सोच पायीं कि जितना शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन, जहाजरानी इत्यादि में सुधार और बदलाव की जरूरत है, उतना ही जातिवादी समाज में। देश की तरक्की जल, थल, वायु, नदी और समुद्र से ही नहीं होती बल्कि नागरिक करते हैं। जापान, कोरिया, आदि देश ऐसे हैं, जहां पर उपजाऊ जमीन नाम-मात्र की है। समतल जमीन भी नहीं है और लगभग 80 प्रतिशत भूमि कंकरीली, पथरीली और पहाड़ी है। 40 साल पहले दक्षिण कोरिया भी विकास के मामले में हमारे ही साथ था, लेकिन आज वह कई गुना आगे निकल गया है। 2016 का अगर कोरिया के साथ जीडीपी की पर कैपिटा की तुलना करें तो उनकी 27,539 डॉलर है तो हमारी 1704 है। जातिवादी मानसिकता के लोग अगर यह भी पढ़ लें तो शायद उनके हृदय में कुछ परिवर्तन हो जाए। इन देशों में क्या मूंछ रखने पर एक नागरिक दूसरे नागरिक को सजा देता है या गरबा देखना जुल्म है? क्या इसे हम कानून-व्यवस्था से जोड़कर देखते रहेंगें?

इन घटनाओं से हमारी पढ़ाई- लिखाई पर भी प्रश्नचिन्ह लग जाता है। लाखों कॉलेज और स्कूल हैं, हजारों इंजीनियरिंग कॉलेज और सैकड़ों विश्वविद्यालय। सैकड़ों टेलीविजन चैनल और अखबार और उसको चलाने वाले हजारों पत्रकार व बुद्धिजीवी। लाखों शिक्षक, लेखक, चिंतक हैं। हमारे यहां इतना भी कम नहीं है शिक्षा का दायरा और बुद्धिजीवियों की संख्या। मान लिया जाए कि राजनीति फेल हुई है तो बुद्धिजीवी तो और भी असफल रहे हैं। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र छेड़खानी और भेदभाव में दूसरों से कम नहीं हैं तो ये शिक्षक क्या इनकी सही मानसिकता बनाने में सफल हो सके हैं? किसी विषय का ज्ञान देना और छात्र परीक्षा में पास हो जाए इसका यह मतलब नहीं कि वह शिक्षित है। जितने लोग स्कूल और कॉलेज की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, अगर वही समझ सकते कि अपनी गंदगी को खुद साफ करना है तो अब तक देश बहुत हद तक स्वच्छ हो चुका होता और प्रधानमंत्री को स्वच्छ भारत अभियान चलाने की आवश्यकता न होती।

स्टाइलिश मूंछ रखने पर प्रताड़ना के विरोध में अब गुजरात के दलित नौजवान ट्वीटर और फेसबुक पर पीयूष परमार एवं संविधान के समर्थन में हैशटैग इस्तेमाल कर रहे हैं, यह कहते हुए कि जातिवादी मानसिकता के लोग यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इससे समाज में कटुता पैदा हुई और जो शक्ति उत्पादन और विकास में लग सकती थी, वह उसके विरोध में खर्च हो रही है। ऐसी घटनाएं जब बृहद रूप लेती हैं तो समाज और बंटता है, अदालतों पर बोझ बढ़ता है और मीडिया में भी जगह देना पड़ता है तो अंततः क्या केवल शोषित वर्ग की ही क्षति होती है। इससे भी और बड़ी क्षति होती है, जैसे कि राजनीतिक ध्रुवीकरण। जहां धुआं है, वहां आग होगी ही। ऐसे में क्यों न शोषित समाज की जातियां अपनी रक्षा के लिए गोलबंद न हों? जब ये गोलबंदी होगी तो विकास की बात पर वोट व चुनाव इत्यादि भी नहीं होगें। क्यों नहीं ये सवर्णों और दबंगों की चिंता होती। शासन-प्रशासन, व्यायपालिका, शिक्षा जगत आदि में इनकी भागीदारी ज्यादा है तो यह माना जा सकता है कि ये शिक्षित और जागरूक ज्यादा हैं। जो ज्यादा शिक्षित और जागृत हैं, उसको ज्यादा देशहित में जिम्मेदार होना चाहिए, इसलिए दलित, पिछड़े व महिलाओं से ज्यादा कहीं उन्हें आगे आकर जवाब देना चाहिए। दुर्भाग्य से अभी तक ऐसा देखा नहीं जा रहा है।

***

हम सरकार पर दबाव बनाने की शक्ति कहाँ से पाएंगे!- डॉ. उदित राज

एच. एल. दुसाध

मित्रों, एफबी पर विगत दो तीन सप्ताह से कई बार लिखा हूँ कि हम आजाद भारत की हिस्ट्री के सबसे भयावह दौर से गुजर रहे हैं। इस दौर में लाभजनक सरकारी उपक्रमों को बेचने के साथ-साथ बैंक, सरकारी अस्पताल, रेलवे इत्यादि को निजी क्षेत्र के हाथों में देने की पुख्ता जमीन तैयार की जा रही है। इस दौर में सुरक्षा तक से जुड़े उपक्रमों में 100 प्रतिशत एफडीआई लागू करने के साथ श्रम कानूनों को कमजोर बनाकर मजदूरों को गुलामों की स्थिति में पहुँचाने का काम चल रहा है। इस दौर में केंद्र सरकार की नौकारियों में 90 प्रतिशत तक की कटौती की जा रही है। ऐसे भयावह दौर में हमारे बुद्धिजीवी क्या मार्ग दर्शन कर रहे हैं, यह जानने के लिए कई संगठनों की संगोष्ठियों में गया और आगे 30 सितम्बर से 1 अक्तूबर तक चलने वाले डॉ. उदित राज के परिसंघ वाले आयोजन में भी जाना है। और खुद से किये गए वादे के मुताबिक कल दिल्ली के मावलंकर हॉल में अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय परिसंघ के दो दिवसीय कार्यक्रम क्रम में शिरकत किया ।

मित्रों यह देख कर मुझे खासा विस्मय हुआ कि जिन शब्दों में आज के भयावह दौर का चित्र मैंने आँका है, प्रायः वही बातें यहाँ भी सुना और और लगभग ऐसी ही बातें 17 सितम्बर को लखनऊ और 24 सितम्बर को दिल्ली के मावलंकर हॉल में सुना था। इसका मतलब यह हुआ कि बहुजन समाज के लेखक, एक्टिविस्ट यह मानकर चल रहे हैं कि मनुवादी आरक्षण के खात्मे की दिशा में अपने लक्ष्य को लगभग हासिल कर चुके हैं। इस कार्यक्रम में डॉ. उदित राज एक बजे के करीब पहुंचे। उनके पहले विभिन्न अंचलों से आये परिसंघ के कार्यकर्ता अपनी बात रखने के दौरान घुमा-फिराकर यही कहते रहे कि आरक्षण खत्म हो रहा है और हमें इसे किसी तरह बचाना है। हमें उम्मीद नहीं थी कि भाजपा से जुड़े होने के कारण डॉ. उदित राज आरक्षण पर गहरी चिंता व्यक्त करेंगे किन्तु, उन्होंने हमें विस्मित करते हुए इस मुद्दे पर वही बातें कहीं, जो हमसब कहते जा रहे हैं। उन्होंने एक जो नई बात कही, वह यह कि हम जब कर्मचारियों को कहते हैं कि आरक्षण खत्म हो रहा है तो अब नहीं कुछ करोगे तो कब करोगे! लेकिन लोग कहते हैं क्या अब आरक्षण को बचाना मुमकिन हैं? बहरहाल उन्होंने उपस्थित लोगों को आश्वस्त किया कि आरक्षण बचाया जा सकता है, बशर्ते हम सत्ता के भरोसे न बैठकर सामाजिक आंदोलनों के जरिये इसे रोकने का प्रयास करें। उन्होंने साफ कहा कि यदि आप यह सोचते हैं कि आपकी सत्ता होगी तभी, यह बचेगा तो यह ठीक नहीं है। यदि बचाने की ललक हो तो सामाजिक आंदोलन चलाकर बचा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने रेल रोक कर आरक्षण हासिल करने वाले जाटों, गुजरात के पटेलों और महाराष्ट्र के मराठों की मिसाल दिया। उन्होंने लोगों का भरोसा बढ़ाते हुए कहा कि हमने अपने प्रयास से निजी क्षेत्र पर आरक्षण के लिए बिल संसद में रखवा दिया है। समस्या बस यह है कि हम इसके लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए शक्ति कहा से लायें! इसकी लाचारी पीड़ा उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। इसके लिए उन्होंने उपस्थित लोगो से आह्वान किया कि आप रामलीला मैदान भरवा दें, फिर शायद हमलोग सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो जायेंगे।

दीप प्रज्वलित करते हुए डॉ. उदित राज जी के साथ एच.एल. दुसाध, सविता कादियान पंवार, ओमप्रकाश सिंघमार, राजेश प्रजापती, परमेंद्र एवं सत्यप्रकाश जरावता

मैं मंच पर उनके बगल में ही बैठा था। उनके उद्घाटन भाषण के बाद मीडिया वाले उन्हें मंच पर ही घेर लिए। उनमें से कईयों ने कहा कि जब आप खुद बीजेपी में हैं तो कैसे आरक्षण बचाने की लड़ाई कामयाबी से लड़ पाएंगे। उनके जवाब से पत्रकार और उपस्थित लोग संतुष्ट दिखे, ऐसा मुझे लगा डॉ. उदित राज ने आरएसएस के कार्यकर्ताओं के समर्पण की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए, उनसे प्रेरणा लेने की अपील हॉउस से की। आर.एस.एस. के कार्यकत्ता अपने मकसद के लिए पूरा जीवन लगा देते। वे अपने लिए कुछ नही चाहते बल्कि हिन्दुत्व के लिए जीते-मरते हैं। विजय दशमी के दिन इस कार्यक्रम को रखने के पीछे युक्ति खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि आज ही के दिन बाबा साहेब ने सामाजिक बदलाव की एक नयी क्रांति का आगाज नागपुर से किया था, इसीलिए हमने दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के लिए यह खास दिन चुना है ।

सम्मलेन में वर्ष 1956 बैच के वरिष्ठ आइएएस पी. एस. कृष्णन की उपस्थिति चौकाने वाली रही । उनका परिचय करते हुए डॉ. उदित राज ने बताया कि कृष्णन साहब दलित नहीं है, किन्तु दलितों के हित में जितने मूल्यवान सुझाव अबतक दिए हैं, वैसा कोई दलित अधिकारी भी नहीं कर पाया। बहरहाल कृष्णन साहब ने अपने संबोधन में कुछ ऐसी बातें कहा जिसका सभागार में उपस्थित लोगों का खासा उत्साहवर्द्धन हुआ। उन्होंने कहा आपके आन्दोलन का लक्ष्य समता मूलक समाज है। इसका लक्ष्य सोशल इक्वेलिटी और रास्ता सोशल जस्टिस है। इसके लिए उन्होंने कई रोचक उदाहरण गिनाये।

बहरहाल इस आयोजन की सबसे बड़ी उपलब्धि VOB NEWS24 चैनल की शुरुआत रही। डॉ. उदित राज ने जुलाई में लखनऊ के रवीन्द्रालय में ऐसा करने का एलान किया था, जो आज पूरा हो गया। इसकी शुरुआत करते हुए उनकी खुशी का अंत नहीं रहा । उन्होंने प्रसंगवश एक ऐसी सूचना से अवगत कराया, जो मेरे लिए नयी थी। सूचना यह थी कि वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ ने , वायर नाम से एक वेब चैनल शुरू किया है, जिसके दर्शकों की सीमा 1 करोड़ तक हो गयी है। उन्होंने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि चैनल के 200 जिलों में पत्रकार नियुक्त होंगे और यदि आपने अपना दायित्व सही तरह से निभा दिया तो अखबार और चैनलों को लेकर समाज में जो रोना-धोना लगा रहता है, वह खत्म हो जायेगा। उन्होंने इसके विषय में जानकारी देते हुए बताया कि चैनल का रिपोर्टर/प्रतिनिधि परिसंघ का नियमित सदस्य ही हो सकता है, अन्य कोई नहीं। ऐसे रिपोर्टर को सोशल मीडिया (जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सप इत्यादि) के उचित ज्ञान के साथ हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा का भी जानकार होना होगा। एक खास बात जो उन्होंने बहुत जोर देकर कही , वह यह कि चूँकि चैनल समाज के द्वारा प्राप्त आर्थिक सहयोग से चलेगा इसलिए प्रतिनिधि को परिसंघ के प्रति समर्पित भाव से अपने स्वयं के खर्चे से अपने क्षेत्र का न्यूज/विडियो/फोटो इत्यादि भेजना होगा। प्रतिनिधियों को किसी तरह की सैलरी भत्ता नहीं दिया जायेगा। उनके इस मार्गदर्शन के बाद एक एक्सपर्ट नौजवान सोशल मीडिया व चैनल के ओपरेशन से अवगत कराने के लिए मंच संभाला और इतने विस्तार से रोशनी डाला कि मेरा भाषण ही नहीं हो पाया। कार्यक्रम का समय ही समाप्त हो गया।

***

परिसंघ के VOB News24 चैनल .....

पृष्ठ 4 का शेष

विराट(सोशल मीडिया इंचार्ज), उत्कर्ष (कैमरामैन), विमल कुमार कमल(कैमरामैन), राशिद (वीडियो एडिटर), करन कुमार कमल(फोटो जर्नलिस्ट) आदि लोग मौजूद रहे।

रामलीला मैदान, दिल्ली में होने वाली आगामी रैली में निम्नलिखित लोगों ने सहयोग करने की मंच से घोष्णा की –

1. सत्य नारायण (दिल्ली) 1 लाख लोग व एक लाख रूपये
2. एम.एस. लाकरा (दिल्ली) 100 गाड़िया (बस व टेम्पो) के साथ लोग
3. चतर सिंह रछोया (दिल्ली) 10 बस व भारी संख्या में लोग
4. पी. बाला (पश्चिम बंगाल) 3 लाख रूपये एवं ज्यादा संख्या में लोग
5. नीरज चक (उ.प्र.) 5 लाख रूपये व एक लाख लोग
6. एस. करूपइया (तमिलनाडु) 10 लाख रूपये व अधिक संख्या में लोग
7. आर.के. कलसोत्रा (जम्मू व कश्मीर) एक लाख रूपये 1000 लोग
8. मधुसूदन कुमार (झारखंड) 50 हजार रूपये व दो रेल बोगी के साथ लोग
9. जे.पी. भास्कर (औरैया, उ.प्र.) 1 लाख रूपये व 1000 लोग
10. शिवधर पासवान (बिहार) 25 हजार रूपये व 2000 लोग
11. नारायण चरन दास (उड़ीसा) 1 लाख रूपये व 2000 लोग
12. सिद्धार्थ भोजने (महाराष्ट्र) 1 लाख रूपये व 2000 लोग
13. परम हंस प्रसाद (म.प्र.) 1 लाख रूपये एवं 1000 लोग
14. हर्ष मेश्राम (छत्तीसगढ़) 1 लाख रूपये व 1000 लोग
15. सत्य प्रकाश जरावता (हरियाणा) 1.5 लाख रूपये व भारी संख्या में लोग
16. प्रताप सिंह अहिरवार (नसोसवाईएफ) 25 हजार छात्र
17. इन्द्रेश चंद सोनकर (खटीक सेना) 50 हजार रूपये व 10 हजार लोग
18. अर्चना भोयर (नागपुर) 40 हजार रूपये एवं 400 लोग
19. सविता कादियान पवार (महिला परिसंघ) ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाएं
20. निर्देश कुमारी (मुरादाबाद, उ.प्र.) 2000 लोग
21. राम प्रकाश (सीतापुर, उ.प्र.) 10 हजार रूपये एवं 500 लोग
22. विजय (उत्तराखंड) 50 हजार रूपये व 3 गाड़ियों के साथ लोग
23. अमर ज्योति (नसोसवाईएफ,बिहार) 1000 छात्र
24. बॉबी पायलेट (हैदराबाद, तेलंगाना) 2 हजार लोग
25. जी. टीका राम (तमिलनाडु) 50 लोग
26. निहाल चंद (हिमाचल प्रदेश) 25 हजार रूपये
27. जितेन्द्र (मुजफ्फर नगर, उ.प्र.) एक बस लोग

– प्रशांत राव गौतम,मो.9935773987

देशभक्तों पर नहीं, दलितों पर चली थी गोलियां जलियांवाला में

हमारे देश के इतिहास को जितना जातिवादी लोगो ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है शायद ही दुनिया के किसी और देश में किया हो, दरसल यह सब एक साजिश के तहत किया गया ताकि इस देश के मूल निवासी अपना सही इतिहास नहीं जान पाए जिस जलियावाला काण्ड को हम यह कह कर पढ़ते है की वहां पर देशभक्तो की कोई देश की आजादी के लिए मीटिंग हो रही थी दरअसल वहां पर देशभक्तों की नहीं दलितों की मीटिंग हो रही थी जो अपने उपर जातिय भेदभाव के मुद्दों पर विचार करने के लिए इकट्ठे हुए थे।

जालियांवाला हत्याकांड के

मुजरिम जनरल ड्वायर को उच्च जाति के बड़े–बड़े महान क्रांतिकारीयों ने क्यों नहीं मारा? दलित उधमसिंह ने ही क्यों उसे लंदन में घुसकर मारा? तो इसका जवाब प्रोफेसर गुरनाम सिंह ठेस सबूतों के हवाले से बताते हैं कि जालियाँवाला बाग में उन दलित सिखों ने सभायें ली थीं जिन्हें स्वर्णमंदिर में घुसने नहीं दिया गया था जहाँ वे प्रथम विश्वयुद्ध में भाग लेने के बाद सकुशल बच आये थे और गुरु का शुक्रिया अदा करने स्वर्ण मंदिर अर्थात सवर्ण मंदिर गये थे। उनपर गोलियाँ जनरल ड्वायर ने किनके कहने पर चलायीं थी? उत्तर है सवर्ण लोगों के कहने पर जनरल डायर ने चलायीं थी। दुर्घटना के बाद जनरल डायर का इन्हीं लोगों ने सरोपा देकर सम्मान भी किया था। इतिहास से यह सब गायब है। जनरल डायर को मारना जरुरी था पर चार योनि वाले ब्रह्मा को मारना उससे ज्यादा जरुरी है। इतिहास में हम दफन है और इतिहास दफनाने वालों का पढ़ाया जाता है।

http://www.januday.com/NewsDetail.aspx?Article=8437

***

महिलाओं की भागीदारी से ही सशक्तिकरण संभव

नई दिल्ली, 24 सितम्बर 2017, अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में राष्ट्रीय संयोजक महिला प्रकोष्ठ सविता कादियान पंवार ने परिसंघ की महिला प्रकोष्ठ की ''एकदिवसीय महिला सशक्तिकरण एवं आरक्षण एक सामाजिक सुरक्षा'' परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन सत्याग्रह मंडप, गाँधी स्मृति एवं दर्शन समिति, राजघाट में आयोजित किया जिसमें मुख्य अथिति राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉ.उदित जी को आमंत्रित किया। पिछले कुछ समय में पूरे देश के अलग–अलग कोनों में दलित महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार और शर्मसार करने वाली घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। जिसे देखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया कि आखिर कब तक दलित महिलाएं इस अत्याचार की पीड़ा को सहन करेंगी और उन्हें कब भागीदारी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में पूरे देश के विभिन्न प्रान्तों से सैकड़ों दलित महिलाओं ने हिस्सा लिया।

परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. उदित राज ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण सिर्फ सोचने मात्र से नहीं हो सकता बल्कि उन्हें पुरुषों की ही भांति बराबरी का अधिकार देना पड़ेगा। यह देश हजारों वर्षो से पुरुष प्रधान रहा है और महिलाओं को हमेशा से ही अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा है और अभी भी ग्रामीण इलाकों में स्थिति जस की तस बनी हुई है। सिर्फ दलित ही नही सवर्ण जाति की महिलाओं को भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर का सपना था कि महिलाएं चाहे दलित समाज से हों या सवर्ण समाज से, सभी वर्ग की महिलाओं को बराबर का सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। बाबा साहब का मानना था कि इस देश की आधी आबादी महिलाओं की है यदि उनकी भागीदारी नहीं होगी तो देश का विकास संभव नहीं हो सकता है । डॉ उदित राज ने आगे बोलते हुए कहा कि मैं खुद कई देशों में गया हूँ और वहां देखा है कि किस प्रकार महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर है और कहीं–कहीं तो पुरुषों की तुलना में ज्यादा भागीदारी महिलाओं की देखी जा सकती है ।

दीप प्रज्वलित करते हुए डॉ. उदित राज जी के साथ सविता कादियान पंवार, आर्चना भोयर, ममता जी, आर्चना जी, उषा मधुसुदन, उर्मिला कच्छप व अन्य

कार्यक्रम का नेतृत्व परिसंघ की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय संयोजिका सविता कादियान पंवार ने किया और सभी महिलाओं को साथ आने व जुडने के लिए सविता जी ने आह्वान किया। मंच का खूबसूरत संचालन दिल्ली प्रदेश का नेतृत्व कर रही श्रीमति सुनीता केम जी ने किया। कार्यक्रम की शुरूआत बाबा साहेब डॉ.भीमराव अम्बेडकरजी व सावित्री–बाई फूले जी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करके शुरू किया व सभी महिलाओ ने कहा कि डॉ. उदित राज व सविता कादियान पंवार के नेतृत्व में हम इस मुहिम को और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। जो महिलाएं शिक्षा से वंचित रह जाती हैं उनके लिए आज के समय में जीवनयापन करना बेहद मुश्किल काम हो रहा है और उन्हें न ही कोई अधिकार दिया जाता है और न ही पुरुषों की तरह भागीदारी । ऐसे में हम सबको मिलकर अपने लिए ही नहीं बल्कि उन वंचित महिलाओं के अधिकार और सम्मान के लिए आवाज उठाने की जरुरत है। इस कार्यक्रम में दिल्ली से रीटा सरकार, नागपुर से अर्चना भोयर, निर्भया कांड आन्दोलन में प्रमुख समाजसेवी योगिता भयाना, झारखण्ड से उर्मिला कच्छप और ऊषा मधुसुदन जी ,संगीता रवि जी, डॉ. बरूआ जी, बिहार का नेतृत्व कर रही ममता जी, हरियाणा से सावित्री जी पंजाब से नवीण जी ने भी कार्यक्रम में भाग लिया व असंख्य महिलाओं की भागीदारी रही ।

– सविता कदियान पंवार
राष्ट्रीय संयोजक
परिसंघ महिला प्रकोष्ठ
मो. 9873944026

Appeal to the Reeaders

You will be happy to know that the Voice of Buddha will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through bank draft in favour of **"Justice Publication"** at T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in **'Justice Publication' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi** under intimation to use by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution :
Five Year : Rs 600/-
One Year : Rs. 150/-

Moustache Monologues: Why the mooch matters

Whether it's stache selfies or the cool confidence of Bhim Army chief Chandrashekhar with his Aviators and handlebar mooch, style has become a way of expressing selfhood for Dalit youth

Last week, a teenaged boy was attacked in Limbodara, in Gujarat's Gandhinagar district, for daring to wear a moustache that suggested his masculinity was on par with that of his Darbar-caste neighbours. Whether it's stache selfies or the cool confidence of Bhim Army chief Chandrashekhar with his Aviators and handlebar mooch, style has become a way of expressing selfhood for Dalit youth

The attackers were trying to invoke an ancient caste privilege. But immediately after the assault, Dalit men across the state and beyond began sharing selfies of their own staches, changing their social media pictures to a sign that said 'Mr Dalit', with a crown and a glorious moustache above it. If the attackers were trying to repress Dalits, they did the opposite – making the upturned moustache the symbol of Dalit assertion.

This is the same macho confidence and cool that Bhim Army founder Chandrashekhar 'Ravan' had patented, when he put up his 'Great Chamaars' signboard in Saharanpur and mobilised his motorbike-riding Ambedkarite comrades.

Chandrabhan Prasad, entrepreneur and thinker, describes it as a new and very different kind of assertion. "It is not about hiding your identity or being afraid, or taking people to court for using caste names. Now they're saying, we're chamar and we're great," says Prasad. How one looks and what one wears is crucial to this assertion. "Dalits have to claim status, to prove society wrong. Thakurs and Jats don't need to dress up, to get others to do salaams. But the idea that Dalits are dirty was a huge historical burden for my generation, and their hard labour left them little leisure to groom themselves or look good. But now, for the generation that has grown up in cities, or been exposed to jobs in factories and services, it's changed." For many historically oppressed groups, style can be about conveying selfhood. If African Americans used their "cool" to show defiance and contempt rather than deference, a Dalit who chooses to wear a Western outfit is casting his lot with modernity and individual agency, rejecting caste stranglehold.

No one was more aware of the social power of apparel than BR Ambedkar, who wore three-piece suits, in stark contrast to Gandhian khadi, and exhorted Dalit men and women to dress at least as well as the upper castes. The recent Tamil movie Kabali carried on that proud spirit, with Rajnikanth as an indentured-worker-turned-don in spiffy suits and sunglasses declaring that his clothes were his resistance. "Kabali incorporated some everyday struggles and politics in Tamil Nadu. While there is no outright opposition to a Dalit in decent clothes, there is definitely some suspicion and discomfort," says C Lakshmanan, associate professor at the Madras Institute of Development Studies.

"It makes the blood of upper castes boil," says Jayanti Makadiya of the Gujarat Dalit Sangathan. "Jab ghulam rehte hain to kuch nahi hota hai (When people stay enslaved, it's all fine). But as social consciousness grows, people find the courage to live like others and this awakening is the reason that attacks happen," he says.

In the graded inequality of Indian society, castes have always been demarcated by elaborate rules on what to eat and wear, how to move and where to live. "In Gujarat, we could not wear full-length chornos and dhotis or grow moustaches. We had to carry our shoes in our hands in the presence of upper castes. A dhoti could not have a border," says Makadiya. Lower castes were made to wear their abjection on their bodies, across India. While the doms were only permitted to wear the cast-offs of the dead, Mahars had to identify themselves with a black thread around their necks. Women could not wear gold jewelry, and wore iron or silver, if at all. "If a women was wearing a thick anklet, she was likely to be lower caste, while upper caste women decorated their noses and ears with jewelry. Dalit women often wore a longer, baggier kameez rather than a blouse, and wrapped their saris differently, sometimes with a tie around the waist to let them work more easily," says Prasad. Kerala had one of the most elaborate sign systems for caste differentiation, which included clothing, jewellery, hairstyles, names and food. Your caste determined how close you could stand to a Brahmin, or if you could even be within their sight and hearing. Lower castes were not allowed headgear or umbrellas, the women could not cover their upper bodies in the presence of 'melajati' upper caste men. If you had the presumption to grow a moustache or cover your upper body, you had to pay a tax to the ruler. Kerala saw a series of agitations, from the Channar rebellion for women's right to cover their chests, to the 1915 Ayyankali-inspired protest where Pulaya women cast away their kallumalas (stone bead necklaces), symbols of an oppressive identity. But for the most part, the visual markers of caste have been obliterated by modernity and consumerism. Most Dalits wear jeans, shirts and dark glasses, and the young women are fashion-conscious. "Nobody is working in the landlord's field any more, they're dressing up their bikes, wearing good clothes," says Prasad. With no nostalgia for traditional attire, Dalits have every reason to be fashion-forward. And this impression of panache has made other communities insecure; recall the PMK's Vanniyar leader S Ramadoss warning of Dalit men "luring" away upper caste women.

These tussles are getting more intense because of the ascendance of reactionary and right-wing forces, says Lakshmanan. "Those who attacked the boy in Limbodra were clearly told by their elders that in the old times, one could punish a Dalit for having a moustache – it has not happened in recent memory. These incidents are happening now because a section of Hindu society is nostalgic about their good old days," says Prasad.

But as the moustache-twirling statement by Dalits makes clear, there's no going back on freedom and dignity.

https://timesofindia.indiatimes.com/home/sunday-times/moustache-monologues-why-the-mooch-matters/articleshow/60987034.cms?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=TOIMobile

***

Stand Up India plan slowing down: Only 6% of bank branches gave loans to SC/STs

In all, the 42 RRBs have sanctioned Stand Up India loans to 536 people — 97 under the SC head, 32 in the ST category and 407 general category women. Three RRBs have not sanctioned a single such loan to general category women.

Shyamlal Yadav

Every bank has been told that it will be your responsibility to ensure that wherever you have a branch, you have to give loans to two persons in the area — a youth who is a Dalit or an Adivasi, and a woman — to help them start a new enterprise, new business.

That's what Prime Minister Narendra Modisaid at the launch of the Stand Up India initiative in Noida on April 5, 2016.

Records show that 17 months after this assurance, barely six per cent of the 1.3 lakh bank branches have provided Stand Up India loans to Scheduled Caste/Scheduled Tribe individuals. And less than 25 per cent of the branches have provided loans to women in the general category. This is according to data on loans obtained from the Department of Financial Services, Ministry of Finance, by The Indian Express under the Right to Information Act. According to the data received, 21 public sector commercial banks, 42 regional rural banks and nine private sector banks have provided Stand Up India loans to 5,852 SC applicants, 1,761 ST individuals, and 33,321 general category women.

The total loan amount sanctioned across banks is Rs 8,803 crore — so far, only Rs 4,852 crore has been disbursed. Data shows that the 21 public sector commercial banks have together sanctioned Stand Up India loans to 38,111 individuals – 5,559 of them are SC, 1,653 ST and 30,899 general category women. The average amount disbursed to SC/St applicants is Rs 10 lakh while the average for women is Rs 12.27 lakh. Six of these public sector banks have together provided loans to less than 100 SC individuals. And 16 banks have not sanctioned a single loan under the ST category. Of the nine private banks, IndusInd Bank has sanctioned 184 Stand Up India loans to SC individuals while only 12 loans have been provided by the rest. The data provided shows that these nine banks have together sanctioned such loans to only 196 SC, 76 ST individuals and 2,015 general category women. Four private banks and 15 of 42 regional rural banks (RRBs) have not provided a single Stand Up India loan to any SC individual. The private banks are Axis Bank, HDFC Bank, South Indian Bank and The Nainital Bank.

Five private banks – Axis Bank, Federal Bank, ICICI Bank, The Nainital Bank and Yes Bank – have not sanctioned a single such loan to any ST person. Of the 42 RRBs, 33 banks have not sanctioned even one such loan to any ST individual. In the case of SC individuals, 15 have not sanctioned any such loan while the rest account for 97. Karnataka Vikas Grameen Bank tops with 13 such loans.

The RRBs which have not granted a single loan to any SC individual are: Arunachal Pradesh Grameen Bank, Baroda Rajasthan Kshetriya Grameen Bank, Bihar Kshetriya Grameen Bank, Chaitanya Godavari Kshetriya Grameen Bank, Chhattisgarh Kshetriya Grameen Bank, Jharkhand Grameen Bank, Kaveri Grameen Bank, Kerala Grameen Bank, Langpi Dehangi Rural Bank, Pallavan Grameen Bank, Pandyan Grameen Bank, Punjab Grameen Bank, Saurashtra Grameen Bank, Uttar Banga Grameen Bank andUttarakhand Grameen Bank. In all, the 42 RRBs have sanctioned Stand Up India loans to 536 people — 97 under the SC head, 32 in the ST category and 407 general category women. Three RRBs have not sanctioned a single such loan to general category women.

The stated goal of Stand-up India, according to the government's website, is to enable bank loans between Rs 10 lakh to Rs 1 crore to at least one SC or ST borrower and at least one woman per bank branch to set up a "greenfield enterprise." The loan — repayable in seven years — is at the lowest applicable rate of the bank for its rating category.

http://indianexpress.com/article/india/stand-up-india-plan-slowing-down-only-6-of-bank-branches-gave-loans-to-scsts-bad-loans-narendra-modi-4882649/

***

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 20 ● Issue 22 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● Total Pages 8 ● 1 to 15 October, 2017

Discrimination is not related to development

Dr. Udit Raj

Be it atrocities committed on Dalits or discrimination meted out to them, it's not always interrelated to development. Ironically in backward areas there are lesser atrocities, contrary to what is found in developed parts of the country. Recently two incidents happened in Gujarat. First, a dalit lad had kept stylish mustache in village Lambodra and that infuriated the upper castes and he was beaten badly. In another incident at Badarnia in Anand district, Jayesh Solanki, 21 years old, had gone to see Garba dance which couldn't be tolerated by Patel community as a result he was beaten badly and eventually died. Needless to say that Gujarat is a developed state. This proves that so called upper caste don't fail to hurl discrimination. The paramount question arises that why only mainly Dalits rise to oppose and not others. Do such incidents affect Dalits only ? Isn't it connected to the overall development of nation and other walks of life like swachh bharat mission and unity of the country.

The mindset which wants to see Dalits, backwards and women excluded and persecuted is the biggest stumbling block in the progress of the nation. Thus, it is not only matter of concern for forces of social justice and backward community but for all. Women constitute nearly half of the population and as long as they continue to be discriminated , their contribution will be negligent in field of education, health and economy. It will not allow to improve the purchasing power of such a vast population that will have a direct bearing on manufacturing, industrialization and service sector. Despite the fact that more than seventy years have lapsed since independence no serious efforts have been made to change the social structure as has been done for the cause of education, health, infrastructure, aviation, IT etc. The progress and happiness of a nation depends not only upon natural resources and endowments such as soil, rivers, mountains, sea and air but also the character of it's citizen. Countries like Korea and Japan are cursed with zig zag land contour, mountains, hills, rivers, earthquakes among other natural impediments yet they have made phenomenal progress. They are not even blessed with the flat land which is a requisite for agriculture and other economic activities and yet see the progress made by these unfortunate island nations. About four decades ago, South Korea was at par with us in terms of per capita income but now it's per capita GDP stands at $27,539 (USD) as compared to $1,704 (USD) for India. If casteist mind realizes this fact there could be some rapid change. Can anyone think of having such a feudal mindset that stylish mustache can potentially infuriate other citizens. Is it only the subject matter of law and order? If parents give preferential treatment to their sons, what politicians and police can do justice. Discrimination and gender separation are largely the product of mindset.

Incidents like the one at Lambodra and Anand create doubt that are we really getting proper education. We have hundreds and thousands of schools and colleges, thousands of professional institutes and hundreds of universities. There are hundreds of television channels which are run by intellectuals and journalists. Millions of teachers, writers, poets, thinkers are in the pursuit of knowledge and education, yet our level of education is on lower side. Considering that politics has not met the expectations, how about our robust education system. Are girl students safe in college and universities? Has the education imparted been able to impact the mind of intellectuals? Have teachers and professors cussed healthy debate and rational thinking? Storing the information in tabula rasa and omitting that in examination does not mean that a person understands the society, meaning of life, freedom, choice and behavior towards others. Let us understand by an example, if the educated had understood the importance of cleanliness and hygiene, that would have itself guided the whole society. It's quite dismal that an educated man distances more from manual and cleanliness jobs.

These two incidents marred the social media and the youth of Dalit started flooding with comments on Twitter, Facebook and Whatsapp. They used hashtag in support of constitution which preaches equality, justice and freedom of choice. Had these incidents not happened, such negative energy would have been applied in production and other constructive fields. Such incidents divide societies and increase workload for the courts which is completely counterproductive. It hampers political debate, free discussion and encourages caste polarization. Smoke often accompanies fire and similarly these atrocities have deleterious effect on progress of nation. Caste polarization outweighs the plank of development. Surprisingly upper caste and privileged fail to realize it. Almost all fields be it administration, judiciary, higher education, industry, manufacturing, finance sector, media are dominated by the so called upper caste and naturally they have access to more knowledge and education. And thus they are more responsible towards the society. Going by any yardstick they are more responsible than SC/ST/OBCs. Should they not come forward to condemn such discriminatory practices? Alas – if they could do now which has not been done till now, it will put India on the path to development and unprecedented progress.

***

20th Maha Rally of The Confederation

On 4th December'17 at Ramlila Ground, New Delhi

The 20th Maha Rally of The All India Confederation of SC/ST Organizations will be held on 4th December'17 (Monday) from 10 AM at Ramlila Ground, New Delhi. All the stake holders of the confederation are requested to start the preparation from today itself. Soon all the resources for advertisement and promotion will reach you via 'Voice of Buddha' and other mediums. All those traveling by rail shall get their reservations done as soon as possible. All State heads are requested to organize a state level summit at the earliest if it has not been done yet. If required I will attend it myself.

To get the latest information about the Maha Rally stay connected via Facebook page of the Confederation by liking the page at www.facebook.com/aiparisangh, follow us on Twitter @aiparisangh and stay tuned to www.vobnews24.com.

Dr. Udit Raj, National Chairman

One Day Convention

On 5th Nov.2017 at Speaker Hall, Constitution Club, New Delhi

All the State Presidents, Gen Secretary's and Activists of Parisangh are informend that they should attend a day long meeting on 5th Nov., 2017 at Speaker Hall, Constitution Club, New Delhi with all details of rally's Preparation, Membership, Achievements, in Social Media etc. Those who have become stringer and reporters of VOB News24, Should also attend with their progress reports.Technical team of VOB News24 will train them.

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: parisangh1997@gmail.com Computer typesetting by C. L. Maurya